32% अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड और बेवरेज प्रोडक्ट डब्ल्यूएचओ से तय क्षेत्रीय सीमाओं के अनुरूप

चंडीगढ़। भारतीय खाद्य बाजार में इस समय उपलब्ध 10,000 से अधिक खाद्य और पेय उत्पादों के हालिया विश्लेषण से पता चला है कि इनमें से लगभग 68% उत्पादों में कम से कम एक चिंताजनक तत्व बहुत अधिक मात्रा में है जबकि 32% खाद्य पदार्थों में यह डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय मानकों के तहत सुझाई गई वैज्ञानिक सीमा के अनुरूप हैं। एक ओर जहां फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फ्रंट-ऑफ-द-पैक फूड लेबल अपनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और उपभोक्ता अधिकार संगठनों ने इस स्टडी का स्वागत किया है। यह स्टडी बताती है कि डब्ल्यूएचओ साउथ एशियन रीजनल ऑफिस का न्यूट्रिएंट्स प्रोफाइल मॉडल भारतीय अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड मार्केट के लिए उपयुक्त और व्यावहारिक है। इसी के साथ यह इंडस्ट्री को नमक, चीनी और सैचुरेटेड फैट पर वैज्ञानिक और साक्ष्य-आधारित सीमा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। एक राष्ट्रीय परामर्श में बोलते हुए, पेपर के सह-लेखक, डॉ चंद्रकांत एस पांडव, पद्म श्री अवार्डी 2021 ने कहा, हमारे अध्ययन में सामने आया है कि एसईएआरओ एनपीएम कट-ऑफ पॉइंट्स को लागू करने से बाजार में मौजूद 68% उत्पादों पर असर पड़ेगा, जिन्हें कम से कम एक चेतावनी लेबल की जरूरत है।

भारतीय खाद्य बाजार में इस समय उपलब्ध 10,000 से अधिक खाद्य और पेय उत्पादों के हालिया विश्लेषण से पता चला है

अध्ययन में सामने आया भारत में 32 प्रतिशत अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड और बेवरेज प्रोडक्ट नमक, डब्ल्यूएचओ द्वारा तय की गई क्षेत्रीय सीमाओं के अनुरूप हैं

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय खाद्य बाजार में इस समय उपलब्ध 10,000 से अधिक खाद्य और पेय उत्पादों के हालिया विश्लेषण से पता चला है कि इनमें से लगभग 68 प्रतिशत उत्पादों में कम से कम एक चिंताजनक तत्व बहुत अधिक मात्रा में है जबकि 32 प्रतिशत खाद्य पदार्थों में यह डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय मानकों के तहत सुझाई गई वैज्ञानिक सीमा के अनुरूप हैं। एक ओर जहां फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफइंडिया फ्रंट-ऑफ-द-पैक फूड लेबल अपनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और उपभोक्ता अधिकार संगठनों ने इस स्टडी का स्वागत किया है। यह स्टडी बताती है कि डब्ल्यूएचओ साउथ एशियन रीजनल ऑफिस का न्यूट्रिएंट्स प्रोफ़ाइल मॉडल भारतीय अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड मार्केट के लिए उपयुक्त और व्यावहारिक है। इसी के साथ यह इंडस्ट्री को नमक, चीनी और सैचुरेटेड फैट पर वैज्ञानिक और साक्ष्य-आधारित सीमा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।भारत गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की तेजी से बढ़ती समस्या का सामना कर रहा है, विशेष रूप से मधुमेह, वयस्कों में मोटापा के साथ-साथ बच्चों के मोटापे में खतरनाक वृद्धि जैसी पोषण संबंधी बीमारियों में तेजी से इजाफा हो रहा है। अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री जितनी तेजी से बढ़ रही है, इसने बाजार में लोगों के लिए उपलब्ध खाद्य विकल्पों को लेकर चिंताएं भी बढ़ा दी है। भारत में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य और पेय पदार्थों की ग्रोथ दुनिया में सबसे अधिक है। अल्ट्रा-प्रोसेस्ड होने के अलावा, इन खाद्य पदार्थों में चीनी, नमक और एडिटिव्स की मात्रा भी अत्यधिक है। 2006-2019 के यूरोमॉनिटर सेल्स डाटा के अनुसार, भारत में पैकेज्ड जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक की रिटेल वैल्यू केवल 13 वर्षों में 42 गुना बढ़ गई है। पिछले एक साल में, एफएसएसएआई सभी पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर अनिवार्य रूप से एफ्ओपीएल शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत फूड इंडस्ट्री को यह सुनिश्चित करना होगा कि चिंताजनक तत्व एक निश्चित सीमा के भीतर है और साथ ही इससे उपभोक्ताओं को सेहतमंद विकल्प चुनने में मदद मिल सके। विश्व स्तर पर 'बिग फूड' इन नियमों का विरोध करने के लिए जाना जाता है, जिसमें विभिन्न दावे किए जाते हैं जैसे कि प्रोफिट मार्जिन पर असर और मूल्य निर्धारण या यह कि सेहतमंद सामग्री नकारात्मक पोषक तत्वों के नुकसान की भरपाई कर सकती है। इस साल की शुरुआत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और चैपल हिल की यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलिना (यूएनसी) के शोधकर्ताओं ने मिंटेल ग्लोबल न्यू प्रोडक्ट डेटाबेस के डेटा का इस्तेमाल किया जिसमें भारतीय खाद्य बाजार के सभी प्रमुख उत्पाद शामिल हैं और इसमें 35,142 उत्पादों को शामिल किया गया है। शोधकर्ता इसमें 10,500 उत्पादों का विश्लेषण कर पाए। इसने न्यूट्रिशन फैक्ट्स पैनल में संपूर्ण पोषण संबंधी जानकारी प्रदान की है। एक राष्ट्रीय परामर्श में बोलते हुए, पेपर के सह-लेखक, डॉ चंद्रकांत एस पांडव, पद्म श्री अवार्डी 2021 ने कहा, हमारे अध्ययन में सामने आया है कि कट-ऑफपॉइंट्स को लागू करने से बाजार में मौजूद 68 प्रतिशत उत्पादों पर असर पड़ेगा, जिन्हें कम से कम एक चेतावनी लेबल की जरूरत है। यह न्यूट्रिशन एल्केमी द्वारा किए गए पहले के एक अध्ययन के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें 1,300 के एक छोटे डाटा का उपयोग किया गया था। इसमें पाया गया था कि 96 प्रतिशत उत्पादों को लेबल की आवश्यकता होगी।

32% अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड और बेवरेज प्रोडक्ट क्षेत्रीय सीमाओं के अनुरूप

भास्कर न्यूज | चंडीगढ़

भारतीय खाद्य बाजार में इस समय उपलब्ध 10,000 से अधिक खाद्य और पेय उत्पादों के हालिया विश्लेषण से पता चला है कि इनमें से लगभग 68% उत्पादों में कम से कम एक चिंताजनक तत्व बहुत अधिक मात्रा में है जबकि 32% खाद्य पदार्थों में यह डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय मानकों के तहत सुझाई गई वैज्ञानिक सीमा के अनुरूप हैं। एक राष्ट्रीय परामर्श में बोलते हुए, पेपर के सह-लेखक, डॉ. चंद्रकांत एस पांडव, पद्म श्री अवार्डी 2021 ने कहा कि हमारे अध्ययन में सामने आया है कि एसईएआरओ एनपीएम कट-ऑफ पॉइंट्स को लागू करने से बाजार में मौजूद 68% उत्पादों पर असर पड़ेगा, जिन्हें कम से कम एक चेतावनी लेबल की जरूरत है। यह न्यूट्रिशन एल्केमी द्वारा किए गए पहले के एक अध्ययन के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें 1,300 के एक छोटे डाटा का उपयोग किया गया था। इसमें पाया गया था कि 96 प्रतिशत उत्पादों को लेबल की आवश्यकता होगी।

32 प्रतिशत खाद्य पदार्थों में चिंताजनक तत्व वैज्ञानिक सीमा के अनुरूप

मुंबई, जेएनएन। भारतीय खाद्य बाजार में इस समय उपलब्ध 10,000 से अधिक खाद्य और पेय उत्पादों के हालिया विश्लेषण से पता चला है कि इनमें से लगभग 68 प्रतिशत उत्पादों में कम से कम एक चिंताजनक तत्व बहुत अधिक मात्रा में है जबकि 32 प्रतिशत खाद्य पदार्थों में यह डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय मानकों के तहत सुझाई गई वैज्ञानिक सीमा के अनुरूप हैं। एक ओर जहां फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फ्रंट-ऑफ-द-पैक फूड लेबल अपनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और उपभोक्ता अधिकार संगठनों ने इस स्टडी का स्वागत किया है।

68 फीसद उत्पादों में चिंताजनक तत्व अधिक मात्रा में

लखनऊ। भारतीय खाद्य बाजार में इस समय उपलब्ध 10000 से अधिक खाद्य और पेय उत्पादों के हालिया विश्लेषण से पता चला है कि इनमें से लगभग 68 फीसद उत्पादों में कम से कम एक चिंताजनक तत्व बहुत अधिक मात्रा में है। जबकि 32 फीसद खाद्य पदार्थों में यह डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय मानकों के तहत सुझाई गई वैज्ञानिक सीमा के अनुरूप हैं। एक ओर जहां फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फ्रंट ऑफ द पैक फूड लेबल अपनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और उपभोक्ता अधिकार संगठनों ने इस स्टडी का स्वागत किया है। यह स्टडी बताती है कि डब्ल्यूएचओ साउथ एशियन रीजनल ऑफिस का न्यूट्रिएंट्स प्रोफाइल मॉडल भारतीय अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मार्केट के लिए उपयुक्त और व्यावहारिक है। इसी के साथ यह इंडस्ट्री को नमक, चीनी और सैचुरेटेड फैट पर वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित सीमा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। वंदना शाह क्षेत्रीय निदेशक ग्लोबल हेल्थ एडवोकेसी इनक्यूबेटर जो सख्ती के साथ एफओपीएल को अपनाने और लागू करने में दुनिया भर के नियामकों की मदद कर रही हैं। उन्होंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि किस प्रकार अपने नागरिकों की बेहतर सेहत के लिए चेतावनी लेबल की शैली में एफओपीएल को अपनाने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है।

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड और बेवरेज प्रोडक्ट नमक, चीनी और सैचुरेटेड फैट की डब्ल्यूएचओ द्वारा तय की गई क्षेत्रीय सीमाओं के अनुरूप हैं

लखनऊ। भारतीय खाद्य बाजार में इस समय उपलब्ध 10,000 से अधिक खाद्य और पेय उत्पादों के हालिया विश्लेषण से पता चला है कि इनमें से लगभग 68त्न उत्पादों में कम से कम एक चिंताजनक तत्व बहुत अधिक मात्रा में है जबकि 32त्न खाद्य पदार्थों में यह डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय मानकों के तहत सुझाई गई वैज्ञानिक सीमा के अनुरूप हैं। एक ओर जहां फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फ्रंट-ऑफ-द-पैक फूड लेबल अपनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और उपभोक्ता अधिकार संगठनों ने इस स्टडी का स्वागत किया है। यह स्टडी बताती है कि डब्ल्यूएचओ साउथ एशियन रीजनल ऑफिस का न्यूट्रिएंट्स प्रोफ़ाइल मॉडल भारतीय अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड मार्केट के लिए उपयुक्त और व्यावहारिक है। इसी के साथ यह इंडस्ट्री को नमक, चीनी और सैचुरेटेड फैट पर वैज्ञानिक और साक्ष्य-आधारित सीमा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

32 फीसदी खाद्य अनुरूप

चंडीगढ़, 3 दिसम्बर (स.ह): भारतीय खाद्य बाजार में 10,000 से अधिक खाद्य और पेय उत्पादों के हालिया विश्लेषण से पता चला है कि इनमें 68 फीसदी उत्पादों में कम से कम चिंताजनक तत्व अधिक मात्रा में है जबकि 32 फीसदी खाद्य पदार्थों में यह डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय मानकों के तहत वैज्ञानिक सीमा के अनुरूप हैं। डॉ. चंद्रकांत एस पांडव, पद्मश्री अवॉर्डी-2021 ने कहा कि हमारे अध्ययन में सामने आया है कि एसईएआरओ एनपीएम कट-ऑफ पॉइंट्स को लागू करने से बाजार में मौजूद 68 फीसदी उत्पादों पर असर पड़ेगा।

CONSUMER VOICE

अध्ययन में सामने आया है कि भारत में 32 प्रतिशत अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड और बेवरेज प्रोडक्ट नमक, चीनी और सैचुरेटेड फैट की डब्ल्यूएचओ द्वारा तय की गई क्षेत्रीय सीमाओं के अनुरूप हंथ

नई दिल्ली,(उदय टुडे)। भारतीय खाद्य बाजार में इस समय उपलब्ध 10,000 से अधिक खाद्य और पेय उत्पादों के हालिया विश्लेषण से पता चला है कि इनमें से लगभग 68 प्रतिशत उत्पादों में कम से कम एक चिंताजनक तत्व बहुत अधिक मात्रा में है जबकि 32 प्रतिशत खाद्य पदार्थों में यह डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय मानकों के तहत सुझाई गई वैज्ञानिक सीमा के अनुरूप हैं। एक ओर जहां फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फ्रंट-ऑफ-द-पैक फूड लेबल अपनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और उपभोक्ता अधिकार संगठनों ने इस स्टडी का स्वागत किया है। यह स्टडी बताती है कि डब्ल्यूएचओ साउथ एशियन रीजनल ऑफिस का न्यूट्रिएंट्स प्रोफ़ाइल मॉडल भारतीय अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड मार्केट के लिए उपयुक्त और व्यावहारिक है। इसी के साथ यह इंडस्ट्री को नमक, चीनी और सैचुरेटेड फैट पर वैज्ञानिक और साक्ष्य-आधारित सीमा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। भारत गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की तेजी से बढ़ती समस्या का सामना कर रहा है, विशेष रूप से मधुमेह, वयस्कों में मोटापा के साथ-साथ बच्चों के मोटापे में खतरनाक वृद्धि जैसी पोषण संबंधी बीमारियों में तेजी से इजाफा हो रहा है। अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री जितनी तेजी से बढ़ रही है, इसने बाजार में लोगों के लिए उपलब्ध खाद्य विकल्पों को लेकर चिंताएं भी बढ़ा दी है। भारत में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य और पेय पदार्थों की ग्रोथ दुनिया में सबसे अधिक है।दावा पेश कर सकते हैं जो उपभोक्ताओं के लिए सबसे आसान, व्याख्यात्मक चेतावनी लेबल के लिए आधार बन सकता है।

'32% of ultra-processed food and beverage products in India meet WHO regional thresholds'

Chandigarh : A recent analysis of more than 10,000 food and beverage products currently available in the Indian food market, has revealed that about 68% of these products have excess amounts of at least one ingredient of concern whereas 32% are within the scientific thresholds recommended WHO regional standards. As the Food Safety Standards Authority of India (FSSAI) prepares to adopt a front-of-the-pack food label (FOPL), public health experts and consumer rights organisations have welcomed this finding which demonstrates that the nutrient profile model (NPM) from the WHO Southeast Asian Regional Office (SEARO) is appropriate and practicable for the Indian ultra-processed food market and may encourage the industry to embrace science and evidence-based cut-offs on salt, sugar and saturated fat. India faces a rapidly escalating burden of non-communicable diseases (NCDs), particularly the rising incidence of nutrition related diseases such as diabetes, obesity among adults as well as an alarming increase in childhood obesity. The simultaneous and exponential growth of the ultra-processed food industry has raised concern about the food choices available to people in the market. India clocks the highest growth rate for ultra-processed food and beverages – items high in added sugar, salt and additives, besides.